भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्या : **2040**

उत्तर देने की तारीख : 28 जुलाई, 2014

**एशिया में भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग**

**2040. श्री गुलाम रसूल बलियावीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत का एक भी विश्वविद्यालय एशिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में शिक्षा तथा अनुसंधान का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या शिक्षा में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): जी, हां। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग, 2014 और क्वाकुआरेली साइमंडस यूनवर्सिटी रैंकिंगः एशिया 2014 के अनुसार, एशिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में कोई भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। रैकिंग की कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियां हैं, जो उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को रैंक प्रदान करने के लिए विभिन्न मूल्यों, सूचकांकों एवं पैरामीटरों का प्रयोग करती है । इनमें से कोई भी प्रणाली वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य नहीं है और प्रायः इनकी आलोचना होती है। जबकि एशिया और विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में स्थान बनाना एक वांछनीय उद्देश्य हो सकता है परन्तु सरकार की नीतियों का फोकस न केवल गुणवत्ता अपितु सुलभता, समानता एवं समावेशिता पर भी होता है ।

(ग): सरकार ने देश में अनुसंधान के स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए हैं। इनमें वैज्ञानिक विभागों के लिए उत्तरोत्तर योजना आबंटनों में सतत वृद्धि,विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान हेतु नई संस्थाओं की स्थापना, अकादमिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते और अग्रवर्ती क्षेत्रों में उत्कृष्टता और सुविधाओं के केन्द्रों का सृजन, नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की स्थापना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी आरएण्डडी भागीदारियों को प्रोत्साहित करना, आरएण्डडी इकाइयों को मान्यता देना तथा उद्योगों इत्यादि को उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देना शामिल है।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन भी करता है जैसे - उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्‍वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज (सीपीई), विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (एएसआईएसटी), मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (एएसआईएचएसएस) बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर) इत्यादि । विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शैक्षिक सुधारों हेतु कई उपाय किए है, जैसे सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, पाठ्यचर्याओं को नियमित तौर पर अधतन करना एवं विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) इत्यादि लागू करना । विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानकों में सुधार करने के लिए "विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्च्तर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय 2010" संबंधी विनियम भी जारी किए हैं । विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने " उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का अनिवार्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन ; विनियम 2012 भी जारी किए हैं जिनमें सभी पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रत्यापन अनिवार्य किया गया है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अपने कार्यक्रमों " विश्‍वविद्यालय अनुसंधान का संवर्धन एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता" (पीयूआरएसई), उत्प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान अनुगमन में नवाचार (इन्सपायर), उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार हेतु निधि (एफआईएसटी) इत्यादि के माध्यम से विश्वविद्यालयों को मुख्यतः अनुसंधान, स्टॉफ लागत, उपकरण सुदृढ़ीकरण एवं संगणक सुविधाओं, अनुसंधान उपभोज्य वस्तुओं तथा सुविधाओं इत्यादि के अनुरक्षण हेतु सहायता प्रदान करता है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी विभिन्न अनुसंधान परिषदों अर्थात भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), भरतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) और भारतीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई) के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और मानविकी में निधियन अनुसंधान भी कर रहा है।

राज्य विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में शिक्षण, अधिगम एवं अनुसंधान के मानकों को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए), एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना (सीएसएस), प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य निर्धारित मानदण्डों एवं मानकों की समरूपता सुनिश्चित करते हुए तथा प्रत्यापन को एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन फेमवर्क के तौर पर स्वीकार करते हुए मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है ।

(घ) और (ड.): जी, नहीं। शिक्षा में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अनुसंधान और विकास का संवर्धन एक सतत प्रयास है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन से चुनौतियां पैदा होती हैं जिसमें हमारे मौजूदा अनुसंधान और विकास सुविधाओं में निरंतर उन्नयन की आवश्यकता रहती है।

\*\*\*\*\*